

## सामाजिक प्रत्युत्तर का फ्रेमवर्क

### अविनाश

अविनाश बायोम सॉल्यूशन्स के साथ काम करते हैं। उनका प्रस्तुतीकरण पानी के संकट से निपटने के संदर्भ में कुछ ग्रामीण व शहरी समुदायों के प्रत्युत्तर पर केंद्रित था।

### अविनाश

मैं बायोम सॉल्यूशन्स और रेनवॉटर क्लब के साथ काम करता हूँ। एक समूह के रूप में हम पानी के मुद्दों पर पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं।

विचार यह है कि हम यहां ऐसे कुछ मुद्दों पर ठोस प्रत्युत्तर पर विचार करें, जिनकी बात शरद लेले ने सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय न्याय दोनों के लिहाज़ से की है। हम समस्या का और बारीक विस्लेषण करना चाहते हैं ताकि यह देख सकें कि विभिन्न हितधारी कौन हैं, उनके प्रत्युत्तर क्या हैं, और हमने इन विशिष्ट प्रत्युत्तरों से मोटे तौर पर क्या सीखा है।

एक समय था जब पानी हमारी सफाई करता था, आज हम पानी की सफाई करते हैं। मेरे ख्याल में भारतीय संदर्भ में यह तथ्य खास तौर से महत्वपूर्ण है कि काफी सारा मीठा पानी भूजल है। भारत में पानी से सम्बंधित मुद्दे के इर्द-गिर्द कुछ मोटी-मोटी बात यह है कि पानी को तीन परिप्रेक्ष्यों से देखा जाता है - सिंचाई क्षेत्र की ओर से, जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में घरेलू पानी।

ऐतिहासिक रूप से सिंचाई क्षेत्र कमोबेश समुदाय-प्रबंधित सिंचाई से शुरू हुआ था, जिसमें मिट्टी की नमी सिंचाई प्रबंधन का एक अहम पहलू था। धीरे-धीरे यह केंद्रीकृत पैनल किस्म की व्यवस्था की ओर बढ़ा जिसमें राज्य की एक प्रमुख भूमिका थी। अंततः इस तरह की सिंचाई व्यवस्था की अक्षमता, खास तौर से यह कि यह व्यवस्था किसानों की सिंचाई सम्बंधी ज़रूरतों को सही समय पर पूरा नहीं कर पाती, के चलते कई आंदोलन हुए। 1990 के बाद के दौर में सिंचाई के एक स्रोत के रूप में भूजल का उदय बहुत तेज़ी से हुआ और अब इसने मूलतः व्यक्तिगत किसान द्वारा प्रबंधित सिंचाई तंत्र का रूप ले लिया है, जिसमें हर किसान बोरवेल खोदकर सिंचाई के लिए भूजल का खनन करता है। कई जगहों पर तो भूजल सिंचाई के बाज़ार हैं।

घरेलू मोर्चे पर प्रमुख मुद्दे पहुंच - पहुंच में समता, समुचित गुणवत्ता के पानी तक पहुंच - और जेंडर से सम्बंधित तथा पानी के बारे में शिक्षा से सम्बंधित रहे हैं। शहरी परिवेश में मेरे ख्याल में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि मांग में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और उसके कारण काफी अभाव व प्रदूषण पैदा हुआ है। इनमें से कई मुद्दे टकराव के संदर्भ में उजागर होते हैं या अपरिहार्य रूप से टकराव को जन्म देते हैं, इन टकरावों में कई आयाम होते हैं, चाहे इसे अधिकार-आधारित परिप्रेक्ष्य से देखा जाए या पात्रता-आधारित परिप्रेक्ष्य से देखा जाए।

प्रत्युत्तर की बात करते हुए, मैं इस बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा कि पानी के संदर्भ में चीज़ें किस ढंग से बदली हैं। पिछले कुछ वर्षों में अंतरगंगे क्षेत्र (कोलार के नज़दीक) की यात्राओं के दौरान हमने रहट का काफी उपयोग देखा। यह एक कृषि प्रणाली है जो काफी हद तक एक उद्वहन सिंचाई यंत्र द्वारा प्राप्त सिंचाई पर आधारित है। पानी एक खुले कुंए से खींचा जाता है; इनमें से उथले वाले कुंए काफी ऊंचे भी होते हैं। मगर मात्र 5-6 सालों से हमने खुद देखा है कि रहटों को हटाया जा रहा है। पहले यह एक ऐसी कृषि प्रणाली थी जो पानी की उपलब्धता के अनुरूप ढली थी, जिसमें कृषि को इस अनुसार किया जाता था कि किस तरह की सिंचाई उपलब्ध है। मगर अब इससे उल्टा हो रहा लगता है। इसे देखकर हम यह सोचने लगे कि उन कुंओं को क्या हुआ। भारत में सभ्यता किसी वजह से खुले कुंओं के इर्द-गिर्द बनी है। मगर हम भूलते जा रहे हैं कि खुला कुंआ क्या होता है, खुले कुंए का मतलब क्या होता है। और शायद हमारी चेतना में से खुले कुंए के विलोप की वजह से सिंचाई में बाकी सारे



परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह सचमुच एक प्रतीकात्मक परिवर्तन है, एक शुरुआत है।

### **पानी के समस्याओं से निपटने के तीन उदाहरण**

आइए, अब वास्तविक प्रत्युत्तर देखते हैं। मैं तीन उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। इनमें से दो ग्रामीण परिवेश से हैं और एक शहरी।

#### **स्कूलों में सरकारी योजना (ग्रामीण परिवेश)**

सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के इस स्कूल को देखिए। यहां कर्नाटक सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य उन ग्रामीण स्कूलों को पेयजल उपलब्ध करवाना था, जहां पेयजल नहीं था। विचार यह था कि इन स्कूलों में छत पर वर्षाजल दोहन की सरल व्यवस्था की जाएगी जिससे पेयजल भी मिल जाएगा। मगर जिस ढंग से पूरी डिज़ाइन की गई थी, उसमें स्कूल के प्रबंधन या बच्चों की कोई भागीदारी नहीं थी। तो अधिकांश मामलों में शिक्षक और बच्चे किसी दिन स्कूल पहुंचकर देखते थे कि एक टंकी बना दी गई है। छत से पाइप टंकी तक आते थे जिससे टंकी छत के पानी के संग्रह में काम आती थी। टंकी बनाने वाला ठेकेदार अपने काम का एक फोटोग्राफ खींचता, सरकार से अपना पैसा लेकर निकल जाता। मगर स्कूलों में जाकर देखें तो टंकियां बुरी हालत में हैं। नल गायब हैं, पाइप टूट-फूट गए हैं।

मैं इस संदर्भ में दो बातें रेखांकित करना चाहूंगा। इन स्कूलों को पानी मुहैया कराने की यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना थी - इसके लिए कर्नाटक के 23,000 स्कूलों को पैसा दिया गया था। स्कूलों से पूछा गया था कि क्या उन्हें पेयजल की ज़रूरत है, उनके यहां पेयजल की समस्या है या नहीं। स्वाभाविक था कि अधिकांश स्कूलों ने हां कहा। इस तरह से यह योजना सारे स्कूलों में चालू हो गई। अलबत्ता, इस योजना के शुरु होने के बाद निगरानी से पता चला कि जिन स्कूलों में इसे लागू किया गया था, उनमें से 57 प्रतिशत में पेयजल की कोई समस्या थी ही नहीं। दूसरी बात, इन स्कूलों के बच्चों या शिक्षकों से बात करने पर पता चला कि टंकियां बनाने से पहले उनसे कोई सलाह-मशवरा नहीं किया गया था। उन्हें तो यह बताया तक नहीं गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है और ठेकेदार ने आकर रातों-रात पाइप और टंकियां लगाए और चल दिया। उदाहरण के लिए, चिकबल्लापुर ज़िले के मल्लसंद्रा में एक स्कूल भाग्यपल्ली के विद्यार्थी आज भी फ्लोरीन-प्रदूषित पानी पी रहे हैं। स्कूल पूरी तरह भूजल-आश्रित है, मगर वहां के पानी में फ्लोराइड है जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। यह वही इलाका है जहां दांतों व हड्डियों में फ्लोरोसिस की समस्या काफी दिखाई देती है। तो यह एक प्रत्युत्तर था।

#### **चार ज़िलों के गांवों में एक कार्यक्रम (ग्रामीण)**

विडंबना देखिए कि राज्य सरकार के उसी विभाग ने उसी इलाके में सचेतना पेयजल योजना नामक एक और योजना शुरू की है। इसका भी मूल विचार वही है, अंतर सिर्फ इतना है कि यह अब परिवारों के साथ काम कर रही है। यह एक संस्था BIRD-K ग्रामीण विकास संस्थान के साथ चल रही है। इस योजना का पैमाना थोड़ा छोटा था। इसे चार ज़िलों के करीब 60 गांवों में पायलट योजना के रूप में लागू किया गया था। संस्था ने लोगों से बातचीत करने, उन्हें सहभागी बनाने, सक्रिय करने और शिक्षित करने के काफी प्रयास किए। सहभागितापूर्ण तरीके को काफी महत्व दिया गया ताकि लोगों से संवाद बनाया जा सके। योजना में विचार यह है कि घरों पर छत के पानी का दोहन किया जाए और लोगों से कहा जाए कि वे इस तरह एकत्रित पानी को भूमिगत या भूमि के ऊपर बनी टंकियों में इस तरह संग्रह करें कि यह साल भर पीने व खाना पकाने के लिए मिल सके ताकि फ्लोराइड-युक्त पानी का उपयोग इन कामों में न हो और उसे अन्य कामों के लिए उपयोग किया जाए। इस योजना के तहत खुद गांववासियों को तय करना था कि टंकी कहां बनाई जाएगी। कुछ लोगों ने टंकी अपने सोने के कमरे के नीचे बनाई है, जबकि कुछ लोगों ने बाहर आंगन में, तो कुछ ने रसोईघर में बनाई है। उन्होंने तय किया कि पानी को कैसे व कहां से निकाला जाएगा। लोगों ने काफी नवाचार का प्रदर्शन किया। कुछ महिलाओं ने तय किया

कि वे छोटे-छोटे हैण्डपम्प लगाएंगी। उदाहरण के लिए, यद्यपि टंकी आगे के आंगन में है मगर उसमें एक पाइप लगाकर हैण्डपम्प को ऐन रसोईघर में लगाया गया है, ताकि यह सिर्फ महिलाओं की पहुंच में रहे और पानी पीने व खाना पकाने के लिए आरक्षित रहे।

लोगों से पानी की गुणवत्ता और इस बारे में बातचीत करने में काफी समय लगाया गया कि टंकी को हर कोई न खोले ताकि कार्बनिक पदार्थों को पानी में पहुंचने से रोका जा सके। एक कोशिश यह भी की गई कि एक बार मटके में पानी भर लेने के बाद क्लोरीन की गोलियों की मदद से उसका क्लोरीनीकरण किया जाए, मगर यह कोशिश बहुत सफल नहीं रही। कई जगह बातचीत में घर की महिलाओं से प्रणाली के बारे में, इसका उपयोग कैसे हो रहा है और उन्हें यह कितनी उपयोगी लगती है, वगैरह के बारे में पूछा गया। कुछेक अपवादों को छोड़ दें, तो यह योजना ठीक से काम कर रही है; इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि इलाके में प्लोरोसिस में कमी आ रही है, हालांकि कुछ परिवारों ने बताया कि वे इस पानी का उपयोग खाना पकाने में नहीं करते क्योंकि पकाते समय पानी उबलता है और प्लोरोसिस दूर हो जाता है। मगर प्लोरोसिस की समस्या इस तरह के किसी भी स्थानीय उपचार से दूर नहीं हो सकती, और इसीलिए वर्षाजल दोहन शुरू किया गया है। तो सारे शिक्षा व संवाद के बावजूद योजना में कुछ खामियां हैं। यह दूसरा प्रत्युत्तर था।

### शहरी परिवेश में वर्षाजल दोहन

तीसरा प्रत्युत्तर शहरी मध्यम वर्गीय परिवेश में है। जिस समुदाय के साथ काम किया गया वह बेंगलूर के बाहरी क्षेत्र में बसा है और उसके पास संस्थागत पानी प्रदाय उपलब्ध नहीं था जो घर-घर पहुंचे। वे पूरी तरह भूजल पर निर्भर थे। उनके पास 5-6 बोरवेल थे जो सूखने लगे थे। लिहाजा रहवासी कल्याण संघ ने पानी प्रबंधन के काम को काफी गंभीरता से लिया। हमने उनके साथ साझेदारी की और एक एकीकृत तरीके से कई कार्य किए। इनमें से एक था अलग-अलग परिवार के लिए वर्षाजल दोहन योजना का निर्माण ताकि कुछ जगहों पर पानी का एक पूरक स्रोत उपलब्ध हो जाए। बस्ती के निवासियों और रहवासी कल्याण संघ ने रीचार्ज कुंए तैयार करने के लिए खुद काफी धन लगाया। मकसद यह था कि वर्षाजल को पकड़कर वापिस भूजल में डाल दिया जाए। बस्ती में पानी भरने की समस्या भी थी; भारी बारिश होने पर कई बार बस्ती के निचले हिस्से में पानी भर जाता था। रीचार्ज कुंओं की पहली खेप लगाने के बाद कम से कम उन्होंने महसूस किया कि पानी का भराव कम हो गया है या पूरी तरह समाप्त हो गया है। इससे काम को बल मिला और कई और रीचार्ज कुंए लगाए गए। अब तक उन्होंने 34 एकड़ भूमि पर 55 कुंए लगाए हैं, और हम अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं क्योंकि आज भी हर सप्ताह कोई न कोई व्यक्ति रीचार्ज कुंए में निवेश करता है।

दूसरा पहलू यह है कि समुदाय के सदस्यों ने वास्तव में बैठकर समझा था कि पानी की उत्पादन लागत कितनी है। हां, उन्होंने पानी की इकोलॉजिकल लागत को हिसाब में नहीं लिया था, मगर उन्होंने उस समझ की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। उन्होंने आंतरिक रूप से तय किया कि वे एक शुल्क नीति लागू करेंगे जो पानी की मात्रा (आयतन) पर आधारित होगी जिससे पानी के संरक्षणमूलक उपयोग को प्रोत्साहन मिले और बरबादी निरुत्साहित हो। इस शुल्क नीति में उन्होंने वर्षाजल दोहन जैसे कामों को बढ़ावा देने के लिए भी उपयुक्त प्रलोभन की व्यवस्था की है।

फिलहाल वे गंभीर रूप से अपजल (waste water) उपचार में निवेश करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं ताकि चक्र पूरा हो जाए और पानी वापिस भूजल में जा सके जहां उसका उपचार करके रीचार्ज योग्य बनाया जा सके ताकि यह चक्र इकोलॉजी की दृष्टि से पूर्ण हो सके।

तो यह एक उदाहरण है जहां वे एक पर्यावरण समस्या से पूरी तरह घरेलू सीमाओं में निपटने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें राज्य शामिल नहीं है। हम खुद से कुछ सवाल पूछते रहे हैं: इस तरह के मॉडल

का मतलब क्या है? इस तरह के विकेंद्रीकृत समुदाय-वालिit पानी प्रबंधन को कैसे प्रशासन में रोपा जाए? इसमें क्षमता निर्माण को कैसे लाया जाए?

इस तरह के विशिष्ट प्रत्युत्तरों से हमें सामान्यीकरण करके समझना होगा कि लोगों के साथ काम करते हुए किस तरह का फ्रेमवर्क हमारा मार्गदर्शन करता है। टिकाऊपन के कई आयाम हैं और आप देखेंगे कि सामाजिक टिकाऊपन सबसे निर्णायक है। मगर टिकाऊपन के किसी भी आयाम को पृथक करके नहीं देखा जा सकता, चाहे वह सामाजिक हो, संस्थागत हो, कानूनी हो, आर्थिक हो, इकोलॉजिकल हो या तकनीकी। मगर कहना न होगा कि प्रायः हम तकनीकी टिकाऊपन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे बहुत महत्व देते हैं।

सोचता हूँ आगे इसे चर्चा और सवालों के लिए खुला छोड़ दूँ।

### **शरद**

आपने जो अंतिम उदाहरण दिया जिसमें एक शहरी बस्ती में बोरवेल सूख गए थे और वे रीचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लेकर मेरा एक सवाल है। मेरे मन में जो सवाल आया वह है - उनके बोरवेल क्यों सूख गए थे? मैं सोच रहा था कि क्या इसी तरह से ग्रामीण परिवेश में फ्लोरोसिस के मामले में सिंचाई या खेती भूजल के ह्रास, और फिर फ्लोरोसिस, में एक कारक है?

### **अविनाश**

वास्तव में इसके दो पहलू हैं। यदि आप फ्लोरोसिस की समस्या देखें तो यह बहुत भयावह है और पेचीदा है। ऐसे गांव हैं जहां भूजल का दोहन एक ऐसी परत तक पहुंच गया है जो फ्लोराइड संदूषित है, जबकि अतीत में यह स्थिति नहीं थी। मगर कुछ इलाके ऐसे भी जहां फ्लोरोसिस भूगर्भ-जनित है। दूसरी ओर, शहरी क्षेत्र में, जी हां, यह शहरी भूजल में गिरावट की व्यापक समस्या का एक हिस्सा है। शहरी क्षेत्रों में हम बार-बार देखते हैं कि जब भी किसी इलाके में किसी नए भवन संकुल का निर्माण होता है तो बोरवेल सूखने लगते हैं। निर्माण कार्य सारा पानी खींच लेते हैं।

### **अनवर**

आप विभिन्न मुद्दों की प्राथमिकता के बारे में क्या कहेंगे कि किन्हें उठाया जाना चाहिए? हमें इस पर चर्चा करना चाहिए क्योंकि यह कार्य योजना की दृष्टि का एक खाका प्रस्तुत करता है।

### **अविनाश**

यदि हम स्कूलों के मामले को देखें तो स्पष्ट है कि तकनीकी रूप से तो समाधान पर बखूबी विचार हुआ था। मगर जिस ढंग से इसे लागू किया गया, उसमें कोई सामाजिक या संस्थागत टिकाऊपन नहीं था क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने तंत्रों की ज़िम्मेदारी नहीं ली और स्कूल के लोग योजना में ज़्यादा सहभागी नहीं थे, इसीलिए परियोजना मुंह के बल गिरी।

दूसरी ओर, लगता है कि दूसरे प्रत्युत्तर में लगभग सारे सरोकारों को संबोधित किया गया था। अलबत्ता, परियोजना के आर्थिक टिकाऊपन को लेकर कुछ चिंता है क्योंकि यह मूलतः एक अनुदान-आधारित कार्यक्रम है जहां इसके लिए सरकार ने परिवारों को अनुदान दिया है। कार्यक्रम में उपयोगकर्ताओं का काफी योगदान रहा है। मगर फिर भी, कार्यक्रम को ज़्यादा बड़े पैमाने पर लागू करने में एक बाधा यह मूलतः वित्तीय है क्योंकि यदि परिवार को अपने घर में यह पूरा तंत्र बनाना हो, तो वे आम तौर पर शुरुआती पैसा खर्च नहीं कर पाते।

तीसरे प्रत्युत्तर में, जब हम कॉलोनियों की बात करते हैं तो हम रेनबो ड्राइव का उदाहरण ले सकते हैं जहां यह सवाल उठाया गया था कि रहवासी कल्याण संघ ने जो उपाय किए थे, क्या वे वैध थे? मान लीजिए यदि कल

हम किसी घर को पानी न दे पाएं तो क्या वह परिवार रहवासी कल्याण संघ पर पानी न देने के लिए मुकदमा चला सकेगा? लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। और यह स्पष्ट रूप से एक मामला था जहां कानूनी टिकारूपन पर गौर करना होगा।

### देविका

हम पुणे के बाहर काफी दूर-दराज इलाके में रहते हैं। जब हम वहां घर बना रहे थे, तब हम जानते थे कि हमें पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यह बहुत अलग-थलग इलाका है और वहां कोई सामुदायिक जीवन नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने किया कि एक सर्वे किया, एक बोर खोदा और उसमें पानी निकल आया, जो काफी रोमांच की बात थी। जब हम वहां रहने लगे, तो पानी दो महीनों से ज़्यादा नहीं चला। जून, जुलाई और अगस्त, हमें पता नहीं था कि हो क्या रहा है क्योंकि वहां बारिश तो लगातार होती है, मगर पानी नहीं होता। सितंबर आते-आते पानी पूरा तरह खत्म हो चुका था। तब हमें टैकर पर निर्भर रहना पड़ा। संग्रहित पानी बिलकुल नहीं था। अगले साल हमने सोचा कि हम फिर से सर्वे करेंगे कि हो क्या रहा है। तो एक बार फिर हमने यह देखने के लिए पूरी प्रक्रिया की कि क्या हमने बोरवेल सही जगह खोदा है। यंत्र के सेंसर काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक-ठाक लगता था। हमने वर्षाजल दोहन पर दो हज़ार और खर्च कर दिए, छत पर 3-4 हज़ार वर्ग फुट क्षेत्र का पानी इकट्ठा किया गया। चूंकि यहां पुणे के मुकाबले पांच-छः गुना ज़्यादा बारिश होती है, इस सारे पानी को हमारे बोरवेल की ओर मोड़ दिया गया जो रीचार्ज हो गया। एक बार फिर काफी उत्साह रहा क्योंकि काफी पानी आ रहा था। तो हमने सोचा कि अब कुछ पौध लगाई जा सकती हैं क्योंकि पर्याप्त पानी है। मगर जैसे ही हमने पौधारोपण शुरू किया पानी खत्म होने लगा। पिछले साल अक्टूबर आते-आते एक बार फिर पानी खत्म हो गया। हम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या रहा है और हम क्या कर सकते हैं।

फिर हमारे छोटे से समूह ने सोचा कि एक ही समाधान, अंतिम समाधान यह है कि बड़ी-बड़ी टंकियां बनाई जाएं जिनमें बारिश का पानी भर जाएगा क्योंकि रीचार्जिंग तो काम नहीं कर रहा है।

तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप इसमें सफलता की कितनी गारंटी देते हैं? आप पक्की तौर पर कैसे कह सकते हैं कि यदि मैं किसी बोरवेल को रीचार्ज करूं तो इतने महीनों तक पानी मिलेगा? यदि मैं गणना करूं कि मेरे परिवार को एक साल में कितना पानी लगेगा, तो उसके लिए हमें ऐसी टंकी बनानी होगी जिसमें 3-4 लाख लीटर पानी भरा जा सके। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं इतना पैसा खर्च करके सुनिश्चित कर सकूँ कि मुझे पानी मिलता रहेगा?

### अविनाश

आपके विशिष्ट सवाल का जवाब देने से पहले, एक तो आपने जो कुछ कहा उस पर एक प्रतिक्रिया है। जब हम एकीकृत पानी प्रबंधन पर काम करते थे, मुझे लगता है कि चीज़ों के मांग पक्ष पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जब आप ऐसी जगह पर हैं जहां के गुणधर्म आपने जैसे बताए, वैसे हैं, जैसा कि आपने कहा कि वहां बढ़िया बारिश होती है तो देखने की एक प्रमुख बात यह है कि कौन-सी सही फसलें हैं, ताकि आप पानी की उपलब्धता का तालमेल अपनी फसलों के साथ बैठा सकें।

### देविका

वहां कोई फसल नहीं है, सिर्फ फूल हैं।

### अविनाश

ठीक है। सामान्य रूप से, हां, पानी को टंकियों में भरकर रखना संभव है। वर्षाजल दोहन कभी भी एक संपूर्ण समाधान नहीं होता - यह अन्य चीज़ों के साथ मिल-जुलकर काम करता है। आपके जैसी परिस्थिति में, भूजल

और छत के पानी के दोहन, जिसे आप टंकियों में भरकर रखेंगे और उपयोग करेंगे, का मिला-जुला रूप होगा इसे एक परिस्थिति विशेष और मांग विशेष के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है।

जहां तक रीचार्ज का सम्बंध है, आप कोई गारंटी नहीं दे सकते। जब आप बोरवेल खोदते हैं और पानी खींचते हैं, तब कोई नहीं पूछता कि यह किसका पानी है। तो जो पानी आप रीचार्ज करते हैं, वापिस ज़मीन में डालते हैं, वह बहकर डाउनस्ट्रीम जा सकता है या किसी और के बोरवेल में जा सकता है। इस बात की कभी कोई गारंटी नहीं होती कि पानी बहकर कहां जाएगा। हमारी संपत्ति की सीमाएं ज़मीन की सतह पर समाप्त हो जाती हैं, वे हमारे पैरों के नीचे नहीं जातीं। मगर यह किया जा सकता है, जो गारंटी दी जा सकती है, वह यह है कि डिज़ाइन पानी की उपलब्धता को देखकर बनाई जाए। समीकरण का दूसरा हिस्सा यह है कि अपनी मांग को उपलब्धता के अनुरूप ढालें।

### वेणु

गांव के लोगों और यहां बैठे लोगों, दोनों के स्वार्थों के पहलू हैं। क्या आप ऐसी कोई परिस्थिति जानते हैं - और यह सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं, यहां सबके लिए है - या कोई ऐसा मामला जानते हैं जहां लोग एक ज़्यादा बड़े संदर्भ में एक-दूसरे से बातचीत या सौदेबाज़ी करके किसी सहयोगी समाधान तक पहुंचे हों, जैसे पानी प्रबंधन जैसी किसी संसाधन प्रबंधन समस्या के मामले में? मुझे लगता है कि यदि ऐसा कोई प्रकरण है, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत लाभ उतने स्पष्ट नहीं होंगे, तो शिक्षा के संदर्भ में इससे काफी कुछ सीखा जा सकेगा।

### अविनाश

मैं कहूंगा कि अधिकांश समीकरणों में स्वार्थ का कुछ तत्व तो घुस ही जाता है।

### वेणु

हो सकता है कि यह स्वार्थ सिर्फ पानी से जुड़ा न होकर एक सामान्य स्वार्थ हो।

### अविनाश

ऐसे कई स्पष्ट उदाहरण हैं, जैसे पोपट राव पवार हैं जो महाराष्ट्र के हिवरे बाज़ार में काम करते हैं। यह काम रालेगांव सिद्धि में अन्ना हज़ारे के काम से प्रेरित है। ये ऐसे उदाहरण हैं जहां वाटरशेड, वर्षाजल दोहन और मांग पक्ष प्रबंधन का मिला-जुला इस्तेमाल किया गया है, जहां किसानों ने आगे आकर कहा कि वे गन्ना या अन्य व्यापारिक फसलें नहीं उगाएंगे क्योंकि इसका असर पूरे गांव पर पड़ता है। इस तरह के उदाहरण ज़रूर मिलेंगे।

### अनवर

आदर्श रूप में पानी प्रशासन की बहुत बातें होती हैं। मेरे ख्याल में एक दिक्कत यह है कि जिस संदर्भ में इसकी बातें होती हैं - मूल्य प्रणाली - जो बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आप इसकी बातें करते हैं जैसे पानी सबका साझा संसाधन है। तब हम इस तरह के मुद्दों की बात नहीं कर सकते कि किसे कितना पानी मिलेगा, किस गुणवत्ता का पानी मिलेगा, किस समय मिलेगा वगैरह। मगर जब देखते हैं, तो हम सचमुच उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं जहां निकट भविष्य में पानी प्रशासन की बात की जा सके। सरकार और सिविल सोसायटी और निजी स्वामित्व के बीच ऐसे लोग हो सकते हैं जो पानी के बारे में एक वास्तविक संसाधन के रूप में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें तो यह हवा जैसा लगता है। हम झिंझकते जा रहे थे और पानी हर जगह था। मगर यदि देखें तो हम तेल के लिए झिंझकते जा रहे हैं। और तेल की खूब परवाह की जाती है, कई देशों में यह निजी मिल्कियत में है। मुझे लगता है कि जल्दी ही पानी की कीमत भी तेल के बराबर या उससे आधी होगी, और तब इस मुद्दे पर अलग ढंग से विचार करना होगा। अंततः हम इस सवाल पर आ जाते हैं कि यदि हम पानी प्रशासन के समूचे मुद्दे की बात करना चाहते हैं, तो हमें यह भी सोचना होगा कि हम किस तरह की मूल्य प्रणाली चाहते हैं जिसका केंद्रीय सवाल यह होगा

कि पानी किसका है? एक बार मेरी बात सरकार के एक सचिव से हुई थी जिसने कहा था, 'पानी दरअसल अपने आप में कोई समस्या नहीं है, समस्या तो ज़मीन की है - ज़मीन जिसकी भी होती है, पानी उसी को मिलता है।' मगर यदि आप देखें तो हम भूमि की उच्चतम सीमा के मुद्दे का भी कुछ नहीं कर पाए हैं। और इसलिए, जब तक हम वह नहीं करते, तब तक हम व्यावहारिक समाधान से कोसों दूर रहेंगे, और मुझे लगता है कि यह मोटे तौर पर एक जैसी समस्या है, चाहे आप भूमि सीमा की बात करें, या पानी सीमा की बात करें, या शिक्षा की बात करें, सवाल अंततः यही है कि क्या हम स्वामित्व के लिहाज़ से देखते हैं या क्या हम इसे निजी स्वामित्व की चीज़ मान लेते हैं। दरअसल, सरकार में मुख्यमंत्री तो पानी की भी निजी मिल्कियत को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं। यहां इस मुद्दे पर भी बातचीत होनी चाहिए।

### **अविनाश**

संभवतः पानी प्रशासन में इस वक्त राज्य सबसे अहम किरदार है, और ऐतिहासिक रूप से राज्य इस भूमिका को प्रबंधन या प्रशासन का काम मानने की बजाय सप्लाई काम मानता आया है। मेरे ख्याल में यह प्रमुख समस्या है। यह बात उस प्रमुख मान्यता परिवर्तन का संकेत देती है जो ज़रूरी है।

### **सुब्रमण्यन**

मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने शुरुआत असफलताओं के विवरण से की। यदि हम डिज़ाइन के लिहाज़ से सीखना चाहें, तो आपने 6-7 आयाम सामने रखे हैं। हर मामले में, यदि आप यह पता कर सकें कि किस आयाम में नाकामी हुई है, तो अगली बार हम डिज़ाइन करते हुए इन नाकामियों को चेतावनियों के रूप में ध्यान रख सकते हैं। डिज़ाइन की दृष्टि से सोचने का मतलब ही है कि नाकामियों से बचना। हम सफलताएं साझा करने में तो आगे रहते हैं, मगर नाकामियां साझा करने में पीछे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि, खासकर इस देश में नाकामियों को कठोर दंड दिया जाता है। इस तरह की किसी भी समस्या के किसी भी समाधान के लिए नाकामियों को साझा करना एक अहम घटक है। मसलन, जब आपने बात की कि राज्य पानी के निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, तो इंग्लैण्ड और लातिनी अमेरिका में यह बुरी तरह असफल रहा है। तो हमें उन लोगों के साथ यह जानकारी साझा करना चाहिए जो हमारे देश में निजीकरण की वकालत कर रहे हैं।

### **एस.सी. बेहार**

आपने तीन उदाहरण बहुत बड़े स्तर (मैक्रो स्तर) के दिए, और मैं यह सोच रहा था कि हमने क्या सबक सीखे हैं कि शरद ने पहले जो समस्याएं प्रस्तुत की थीं, उनके समाधान सुझा सकें। इस फ्रेमवर्क में जो समस्याएं प्रस्तुत की गई हैं, उनमें काफी बड़े-बड़े राजनैतिक मुद्दे हैं। मेरे ख्याल में शरद ने यह कहकर समस्या को काफी सरल कर दिया था कि एकाधिक परिप्रेक्ष्य होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है और सुलझाना होता है। मगर ये मुद्दे और परिप्रेक्ष्य आपके प्रस्तुतीकरण में रेखांकित नहीं हुए थे। उदाहरण के लिए, निचले स्तर पर भी राजनैतिक मुद्दे शामिल होते हैं; जब आप रहवासी कॉलोनी में उन मुद्दों से निपटने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग उस योजना या कार्यक्रम विशेष के खिलाफ हों। वहां समूह या गुट हो सकते हैं, जिनका ज़िक्र नहीं हुआ था। निश्चित रूप से, इन तीन उदाहरणों में कुछ सबक हैं, मगर वे बहुत साफ नहीं हैं। क्या आप उनके आधार पर सामान्यीकरण करने में और असफलताओं को समझने में और अंततः उनसे उजागर होती संभावनाओं को देखने में हमारी मदद कर सकते हैं।

### **अविनाश**

किसी समुदाय का उल्लेख एक समुदाय के रूप में करना सरल है। मगर हर समुदाय में अपने विभाजन होते हैं, यहां तक कि हर परिवार में भी अपने विभाजन होते हैं। उस विशिष्ट संदर्भ में वहां एक नेतृत्व मौजूद था और एक

मायने में वहां दो व्यक्तियों की एक चालक शक्ति थी जिन्होंने सुनिश्चित किया कि सब कुछ सुचारु रूप से चले। निसंदेह, उस पूरी प्रक्रिया में उनकी भूमिका निर्णायक महत्व की रही।

मगर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, जब हम इसे पानी से और खासकर भूजल से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि यह पूर्णतः भूजल-चालित परिस्थिति है, तो सवाल यह उठता है कि भूजल नियमन या भूजल प्रशासन की निगरानी या पहरेदारी एक नियामक फ्रेमवर्क में की जाए या यह एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जो स्वार्थों से प्रेरित स्व-नियमन को संभव बनाए? यह उसकी व्यापक व्याख्या है, जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा, आप इस सबक की व्याख्या एक नव-उदारवादी संदर्भ में निजीकरण के मामले में कैसे करते हैं और कैसे इसे वहां जोड़ते हैं? यह एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब देने की मैं इस वक्त तो जुर्रत नहीं करूंगा।

## मीरा

जब हम पानी की बात करते हैं, तो मैं दो श्रेणियों के बारे में सोच सकती हूँ। एक है, पानी एक संसाधन के रूप में, जिसका उपयोग हम खेती में करते हैं, उद्योग में करते हैं। दूसरी है, पानी दैनिक जीवन की एक आवश्यकता के रूप में, जो पानी का घरेलू उपयोग है। अधिकतर समय होता यह है कि पानी प्रबंधन और पानी प्रशासन में प्रति व्यक्ति खपत, शहरों के लिए पानी, निजीकरण, पाइपों में पानी, या किसी ऐसे स्रोत से पानी निष्कर्षण के बारे में बातें होती हैं जो स्थायी रूप से मौजूद है; लगता है समस्या सिर्फ निष्कर्षण और प्रदाय की है। मगर परिवार के स्तर पर जो व्यक्ति पानी लाती है और परिवार के लिए पानी की पूर्ति करती है, वह महिला होती है; यह जेंडर का सवाल है। जब मैं पानी और जेंडर के मुद्दे को थोड़ा और बारीकी से देखने लगी, तो मैंने देखा कि जब पानी परिवार के लिए होता है, तो अधिकांश समय प्रबंधन व अंतर्क्रिया से सम्बंधित मुद्दों को महिलाएं संभालती हैं। मगर जैसे ही यह कोई योजना का रूप लेता है, जैसे स्कूलों में, तो पानी का प्रबंधन पुरुष अपने हाथों में ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान में महिलाओं द्वारा बोरवेल की मरम्मत करने तक के किस्से हैं। तो कहीं न कहीं कई सारे शोधकर्ताओं ने इस जेंडर मुद्दे को उठाया है और इस पर काफी काम हुआ है।

दूसरे, मैं पानी की उपलब्धता को लेकर कुछ कहना चाहती हूँ, जिसे आप वैज्ञानिक ढंग से संभाल सकते हैं - पुनर्भरण (रीचार्ज), भूजल, पानी प्रबंधन, वाटरशेड प्रबंधन - सैकड़ों ऐसी चीजें हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ में एक ग्लोबल वॉटर पार्टनरशिप है जो पानी और नदी के पानी के बंटवारे पर टूल किट पर काम कर रहा है। और कोई चीज़ है जिसे 'पानी तक पहुंच' कहते हैं। राजस्थान में एक बावड़ी है और यह उच्च जाति की बावड़ी है। यह पूरी भरी हो या पानी बहकर जा रहा हो, मगर दलित महिलाओं को यहां से पानी नहीं मिलेगा। एक और उदाहरण कोरामंगला का है, जहां एक एशियाई खेल गांव है। इसके दूसरी ओर तालाब के पेंदे में एक झुग्गी बस्ती है। समृद्ध कोरामंगला कॉलोनी में कुछ लोगों के घरों पर इस झुग्गी बस्ती की महिलाएं नौकरानी का काम करती हैं। वे करती यह हैं कि जिस भी घर में वे काम करती हैं, उनके साथ एक करार कर लेती हैं, जिसमें उन्हें दस मटके पानी ले जाने को मिलता है। वे इसे झुग्गी बस्ती में लाकर चार रुपए प्रति मटके के हिसाब से बेचती हैं। यहां यह वैकल्पिक किस्म की पानी-पहुंच स्थापित हो गई है। और शायद पानी प्रबंधन से जुड़े किसी व्यक्ति ने सोचा तक नहीं होगा कि यथार्थ में ऐसी कोई चीज़ हो रही है। दरअसल, वहां चार सरकारी टंकियां बनाई गई हैं जिनसे पानी आता है। मगर इसकी चाभी एक स्थानीय राजनैतिक महिला नेत्री के पास है। तो यदि आप उससे अच्छे रिश्ते रखें, और एक चिट फंड में निवेश करें, तो आपको पंप चालू करने के लिए चाभी मिल जाएगी। होता यह है कि दोपहर बारह बजे सब लोग सड़क पर कपड़े धोते नजर आते हैं क्योंकि हर किसी ने महिला के फंड में पचास पैसे जमा किए हैं।

तो दो स्तरों पर, जब हम विज्ञान और पानी दोहन की बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हम पानी की उपलब्धता की बात भी कर रहे हैं, और पहुंच से सम्बंधित मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, जिनके राजनैतिक निहितार्थ होते हैं।

मुझे लगता है कि इसीलिए शरद की बात महत्वपूर्ण है कि लोग-प्रकृति-लोग के चक्र पर ध्यान देना ज़रूरी है। सामाजिक जवाबों के बगैर कभी-कभी सिर्फ वैज्ञानिक जवाबों से काम नहीं चलेगा, और सामाजिक जवाब उस ज़माने की राजनीति को शामिल किए बगैर संभव नहीं हैं।

## शरद

इसमें थोड़ा जोड़ते हुए मैं कहूंगा कि इंटरफेस (परस्पर संपर्क का बिंदु) भी दिलचस्प है। पुणे के मेरे एक दोस्त ने सिंचाई के पानी तक पहुंच सम्बंधी एक परियोजना पर काम करते हुए बहुत दिलचस्प समझ हासिल की थी: कि कैसे जिन वैज्ञानिक विश्लेषणों या इंजीनियरिंग नुस्खों का पालन किया जाता है, वे कुछ सामाजिक विचारों द्वारा ढले होते हैं। जैसे हम पानी संग्रह करने के लिए सिंचाई बांध बनाते हैं और फिर इंजीनियर्स नहरों की डिज़ाइन बनाते हैं जिनके ज़रिए पानी का वितरण किया जाता है, और नहर तंत्र आम तौर पर गुरुत्व प्रवाह पर आधारित होता है। तो वे मूलतः बांध के निकास बिंदु के कॉन्टूर स्तर से शुरू करते हैं और नहर उस कॉन्टूर पर आगे बढ़ती है और इसका परिणाम यह होता है कि उस नहर से डाउनस्ट्रीम या निचले क्षेत्र में स्थित हर खेत को पानी मिलेगा जबकि उसके ऊपरी ढलान पर स्थित खेतों को पानी नहीं मिलेगा।

यह खालिस इंजीनियरिंग नज़रिया है। इसमें यह मानकर चला जाता है कि आपकी नहरें गांव के बीच से, खेतों के बीच से गुज़र सकती हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि निचले ढलान के लोगों को पानी मिलेगा और यह इस काम को करने का सबसे कार्यक्षम तरीका है। यह भी दिलचस्प बात है कि कुछ गांवों में जहां आंदोलन हुआ, जैसे सांगली क्षेत्र में, वहां गांववासियों ने पूछा कि क्यों पानी का आवंटन गांव को एक इकाई के रूप में नहीं हो सकता। थोड़ा गांव नहर से ऊंचाई पर हैं और थोड़ा गांव नीचे की ओर हैं मगर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि पूरे गांव को पानी आवंटित करें? और यदि ज़रूरी हो, तो इस आवंटन को संभव बनाने के लिए इंजीनियरिंग में थोड़ा फेरबदल क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने यह तक सुझाया कि यदि ज़रूरी हो, तो वे एक उद्वहन पंप लगाएंगे ताकि निचली ज़मीन के समान ही ऊंचाई पर स्थित ज़मीन पर भी सिंचाई कर सकें। मगर अब तक यह बात इंजीनियरिंग भेजे में नहीं घुसी है क्योंकि वे तो इस नज़रिए के कायल हैं कि पानी उपलब्ध है जिसका वितरण किया जाना है और ऐसा करने का सबसे 'कार्यक्षम' तरीका गुरुत्व प्रवाह है। अर्थात् 'कार्यक्षमता' को एक विशेष ढंग से परिभाषित किया गया है, इसमें समता या टिकाऊपन के लक्ष्य हैं ही नहीं। लिहाज़ा मैं कहूंगा कि यदि व्यापक पानी प्रबंधन में हम टिकाऊपन के सूत्र का उपयोग करते हैं, तो हमें समता व लागत-क्षमता के सूत्रों का उपयोग भी साथ-साथ करना होगा, क्योंकि जब पानी एक उचित कीमत पर मिलेगा तभी एक गरीब व्यक्ति इसे वास्तव में हासिल कर पाएगा। इसे सामाजिक टिकाऊपन कहने की बजाय, शायद हम इन्हें तीनों लक्ष्य - कार्यक्षमता, समता और टिकाऊपन - हासिल करने की रणनीतियां विकसित करने के विभिन्न तत्वों के रूप में देख सकते हैं, जो साथ-साथ काम करेंगे।

अब ज़रा समीकरण के मांग पक्ष पर नज़र डालते हैं। अभी पेयजल और घरेलू पानी के जो उदाहरण दिए गए, उनमें भी एक रोचक बात यह है कि समता के मुद्दे बहुत तल्खी से सिर नहीं उठाते हैं क्योंकि अंततः संसाधनों से आप जो मांग करते हैं वह स्वतः सीमित है। मेरा मतलब, आप दिन भर में कितना पानी पी सकते हैं? या आप खाना पकाने या कपड़े धोने में कितना पानी खर्च करेंगे? मगर जब आप सिंचित खेती की दुनिया में कदम रखते हैं, तो बात अलग हो जाती है, वहीं से तनाव शुरू होते हैं। या यह बात एक सामाजिक अर्थ में उभर सकती है - उदाहरण के लिए आप एक ऐसे अपस्ट्रीम क्षेत्र में बस जाते हैं जहां पहले कोई बस्ती नहीं थी, और अब फूलों के लिए आपकी पानी की मांग बहुत अधिक हो सकती है। फूल बहुत पानी खर्ची फसल होती है, हालांकि वे कृषि फसल शायद न हों।

## देविका

यह इस पर निर्भर है कि मैं कौन-से फूल उगाती हूँ। मैं शायद वे फूल न लगाऊँ जिन्हें बहुत पानी चाहिए। हो सकता है मैं स्थानीय किस्म लगाऊँ - जैसे करोंदा, जो जंगली रूप से उगता है। मगर मैं तो जंगली फूलों को भी नहीं संभाल पा रही हूँ।

## अविनाश

तो एक बार फिर मुद्दा सामाजिक वितरण का हो जाता है। मान लीजिए कोई किसान पहले डाउनस्ट्रीम आया या कोई पहले अपरस्ट्रीम आया - इस संदर्भ में आप समता को कैसे परिभाषित करेंगे? ये बहुत पेचीदा सवाल हैं। मगर जैसे ही मांग पेयजल या कपड़े धोने जैसे कामों से ज़्यादा होने लगती है, ये सवाल उठने लगते हैं। गांवों में तो किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिंचाई के पानी और उसी घर या पड़ोसी की महिला द्वारा घरेलू ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के बीच भी टकराव होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये गांवों के बीच या समुदायों के बीच के टकराव हों। समुदाय के अंदर भी इस तरह के टकराव होते हैं। इस मायने में यह बहुत ही पेचीदा मुद्दा है।



अलबत्ता, थोड़ा-सा और जोड़ता हूँ, किसी ने पूछा था कि सबक क्या हैं? एक सबक तो हमने पाया कि सामूहिक कार्रवाई के विचार का है। उदाहरण के लिए, बेंगलूर में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग एसोसिएशन में जब भी स्वार्थों में समानता होती है, सिद्धांत बताता है कि वहां सामूहिक कार्रवाई के लिए कुछ प्रलोभन होता है, जो फलदायी होती है। ऐसी स्थिति में आप माहौल को प्रशासन से स्वतंत्र रख सकते हैं, जो थोपा जाने की बजाय मददगार ज़्यादा होता है। अन्य स्थितियों में, जहां आपको पानी को विभिन्न समूहों के बीच भी बांटना हो, तब आपको कहीं अधिक थोपने वाला रुख लेना पड़ता है, जिसमें यह कहा जाता है कि 'यह तो बढ़िया है कि आपने सामूहिक रूप से सारा पानी हथियाने का निर्णय किया है, मगर और लोग भी हैं जिन्हें कुछ पानी की ज़रूरत है।' आप सामूहिक रूप से उन लोगों की ज़रूरत को नज़रअंदाज़ करने का निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि सामूहिकता स्वयं को विचित्र रूपों में परिभाषित करती है। ये स्व विकसित होते सामूहिक कार्रवाई के निर्णय प्रायः वितरण के मुद्दों से जुड़े होते हैं, जो उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुख्य बात इस सवाल का जवाब तलाश करने की है - आगे कैसे बढ़ें?

## अंजलि

मैं ऐसे सरोकारों के बारे में कुछ जानकारी पूछना चाहती थी, यह जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जैसे, खपत के पैटर्न किस तरह के हैं? पानी के विभिन्न उपयोगों की प्राथमिकताएं कैसे तय की जाएं? किस तरह की फसलें बहुत ज़्यादा पानी खर्च करती हैं। विभिन्न इलाकों को लेकर अलग-अलग उदाहरण कौन-से हैं? क्योंकि, उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में ऋषि वैली क्षेत्र में वे लोग संरक्षण का काफी काम करते हैं, वानिकी करते हैं और ऐसे कई काम करते हैं जिनसे भूजल स्तर बढ़ता है। और फिर यदि आसपास के किसान एक सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी-खर्ची फसलें उगा रहे हैं, तो वे उनके साथ बातचीत करते हैं।

इसके अलावा, जहां तक फसलों का सवाल है, मध्य प्रदेश में एक ज़्यादा वैश्विक गतिशीलता रही है, एक व्यापक गतिशीलता जो 1990 के दशक की हरित क्रांति से आई है। वास्तव में मध्य प्रदेश के गरीब इलाकों में सोयाबीन का बोलबाला हो गया है, जो कहीं अधिक पानी-खर्ची है। एक समय था जब प्रोटीन की उपज बढ़ाने के लिए ज़्यादा अनुसंधान हुआ था, जिसकी हमें ज़रूरत थी। सब जानते हैं कि आज तुअर दाल की कीमत क्या है। हालांकि लोगों के पास खाने को ज़्यादा तुअर नहीं है मगर वे अपनी फसलों के लिए ज़्यादा पानी खर्च कर रहे हैं। हमें कुछ इस

ढंग से काम करना चाहिए कि सामूहिक लॉबिंग के लिए कुछ विकल्प सुझाए जा सकें। यह एक किस्म की जानकारी है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए।

दूसरा है कि छत के पानी के संग्रहण और पानी के पुनः उपयोग को जोड़कर एक एकीकृत पानी प्रबंधन तंत्र का विकास करना। वे कौन-से तरीके हैं जिन्हें आप एक परिवार के रूप में लागू कर सकते हैं। इसे लेकर पुस्तिकाएं हो सकती हैं। कॉलोनियों में तो ऐसी जगह हो सकती है जहां टंकियां लगाई जाएं। मगर एक-एक परिवार के लिए कितनी जगह लगेगी कि वे वर्षाजल दोहन की टंकी को रख सकें, और इसके लिए कितना पैसा लगेगा? यदि आपके पास ऐसी कोई पुस्तिकाएं या साहित्य हो जिन्हें हम देख सकें, ऐसी चीजों को वितरित करना बहुत अच्छा होगा।

### **अविनाश**

सवाल का पहला हिस्सा काफी पेचीदा है। इस संदर्भ में, जैसा कि आपने सही कहा, समाधान पानी क्षेत्र से नहीं आता। हमें कृषि नीति को देखना होगा, खाद्यान्न, उर्वरक, ऊर्जा और बिजली नीति को देखना होगा और हमारा ध्यान इन मुद्दों पर होना चाहिए तभी हम पानी की समस्याओं को दुरुस्त कर पाएंगे। और जो चीज़ भूमि उपयोग को कम पानी वाली कृषि से हटाकर ज़्यादा पानी वाली कृषि की ओर ले जा रही है, वह अर्थशास्त्र है - किसानों का व्यक्तिगत कृषि अर्थशास्त्र। इस व्यापक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा मैंने पहले की थी। तो मुझे लगता है कि विशिष्ट जानकारी के आधार पर इसका जवाब देना मुश्किल है क्योंकि व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ में हर क्षेत्र की अपनी रंगत और गतिशीलता होती है। मगर फिर यह देखना होगा कि पानी-किफायती फसलें कौन-सी हैं, वे कौन-सी कृषि प्रणालियां हैं जो पानी-किफायती हैं, यह काम कई लोग कर रहे हैं। और यह सब खाद्य दैत्यों से जुड़ जाता है। यह कई अन्य मुद्दों से जुड़ा है जो इस बात पर असर डालते हैं कि ये विधियां व्यावहारिक होंगी या नहीं और यह कहीं ज़्यादा उलझा हुआ आर्थिक मुद्दा है, जिस पर यहां बात करना मुश्किल है।

मगर आपके दूसरे सवाल के जवाब में, जी हां, वर्षाजल दोहन, या इकोलॉजिकल अपजल उपचार के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मगर इंटरनेट पर आपको इन मुद्दों पर काफी सारा साहित्य या विशिष्ट जानकारी मिल जाएगी। [www.rainwaterclub.org](http://www.rainwaterclub.org) पर काफी सारी जानकारी उपलब्ध है। जहां तक पुस्तिकाओं और विशिष्ट जानकारी का सवाल है, आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल पता हमारी वेबसाइट पर है। ऐसे कई और संगठन हैं जो इस तरह की जानकारी दे सकते हैं।

### **सारांश**

प्रस्तुतीकरण पानी प्रबंधन के एक फ्रेमवर्क के विकास से सम्बंधित मुद्दों को समस्या का रूप देने की कोशिश था, किस सीमा तक इसका नियमन व निगरानी की जाए, और किस हद तक यह समुदाय-आधारित होना चाहिए। वक्ता ने इसके लिए पानी की समस्या से निपटने के तीन विशिष्ट उदाहरण दिए, तीनों में वर्षाजल दोहन शामिल था। प्रस्तुतीकरण के अंत में चर्चा में टिकाऊ विकास व समतामूलक वितरण के व्यापक दायरे से कड़ी जोड़ी गई, और यह आग्रह किया गया कि पानी की समस्या को एक संसाधन के रूप में पानी की उपलब्धता, पहुंच व स्वामित्व से सम्बंधित मुद्दों और पानी के निजीकरण के उभरते रुझान के लिहाज़ से देखें।